### सुप्रीम कोर्ट में बार-बार पहुंचता दलबदल कानून

**न्यायशास्त्र** के दो प्रचलित सिद्धांत हैं पहला, कोई कानून सही है या गलत यह पता लगाने के लिए यह देखना चाहिए कि उसके न होने पर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं; और दूसरा, ऐसा कानून, जिसे तोड़कर बचना आसान हो, समाज को लाभ की जगह नुकसान पहुंचाता है। कर्नाटक में सरकार तो बहुमत के अभाव में गिर गई, लेकिन जिस दिन दलबदल कानून को ठेंगा दिखाते हुए 12-15 बागी विधायक मंत्री या अन्य समकक्ष पद की शपथ लेंगे, वह दिन भारत के संविधान की गरिमा के लिए शायद सबसे बुरा दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को सदन में आने न आने की छूट देकर और स्पीकर को व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक के भाग्य का फैसला करने की छूट देकर फैसले में संतुलन बनाने की कोशिश की थी। सरकार तो गिर गई और नियमानुसार नया स्पीकर 14 दिन बाद चुना जाएगा, लेकिन वर्तमान में यही स्पीकर कांग्रेस और जद (एस) की शिकायत पर कॉनूनन 15 दिन के भीतर फैसला लेंगे। उधर बागी विधायकों ने सारी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है- पहले कहा कि उन्हें स्पीकर का नोटिस मिला ही नहीं और अब जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांग रहे हैं ताकि उस समय तक भाजपा का स्पीकर आ जाए और वे शपथ ले सकें। जाहिर है अगले दो-चार दिन में ही स्पीकर यह फैसला करने जा रहे हैं और फैसला क्या होगा यह भी स्पष्ट है। स्पीकर के फैसले को नया स्पीकर नहीं बदल सकता और केवल अदालत ही उसका संज्ञान ले सकती है। यानी मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। अब इसका दूसरा पहलू देखें। अगर स्पीकर यह फैसला न लें तो ये सब मंत्री सहित तमाम सरकारी पदों पर बैठकर पूरे भारत के जनप्रतिनिधियों को संदेश देंगे कि व्हिप जारी होने से पहले इस्तीफा दो और संविधान की अनुसूची 10 (4) (2) के- 'केवल दो-तिहाई बहुमत और साथ में किसी अन्य दल में विलय- की शर्त को अंगूठा दिखाते हुए नई सरकार में मंत्री बन उसी संविधान में निष्ठा की शपथ लो। अगर मैंकॉले की दंड संहिता 259 साल तक भारत-पाकिस्तान में बदस्तूर कायम रह सकती है तो क्यों दलबदल कानून को 2003 में और सख्त बनाया गया और फिर भी हर बार कुछ समय बाद इसे चुनौती देकर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर डाल दिया जाता है। शायद 'माननीयों' को भी अभी अपने ही बनाए कानून के पालन में ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है।

#### आकर्षण नहीं, देह से मुक्त होना प्रेम है



पं. विजयशंकर मेहता humarehanuman@gmail.com

प्रेम विवाह करने वाले आज भी दूसरों की निगाहों में तो आते हैं, लेकिन तमाशा बन जाएं इसमें उनका भी योगदान होता है। यदि किसी से प्रेम है तो विवाह करने में क्या दिक्कत? लेकिन समस्या यहां यह है। कि अधिकांश लोग प्रेम का अर्थ समझ ही नहीं पाते और आकर्षण को ही प्रेम मान लेते हैं। परतमसत्ता या किसी भी व्यक्ति के प्रति जो सात्विक-स्वाभाविक झुकाव होता है, उसे प्रेम कहा गया है। यह मोहजन्य अवस्था नहीं है। प्रेम एक घटना है और इसमें जो पात्र होता है, वह प्रिय होता है से और मिल जाने पर रोम-रोम प्रसन्न व मुक्त होने का विषय है..।

तुप्त हो जाता है, लेकिन इसमें पवित्रता शर्त बनी रहती है, इसके बिना प्रेम प्रेम नहीं हो सकता। अब तो लोग आकर्षण को ही प्रेम मानकर बैठ गए। संस्कृत में एक शब्द आता है- स्नेह। इसका अर्थ होता है चिकनापन और चिकना या तरल पदार्थ जो भी होता है, वह नीचे की ओर ही बहता है। इसलिए आकर्षण स्नेह के निकट होता है। तो जिसमें मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहे, उसमें स्नेह की संभावना अधिक होती है और जिसमें ऊर्जा ऊपर की ओर बहकर हृदय पर टिके, आत्मा तक जाए वहां प्रेम होता है। आज के दौर में चूंकि भोग-विलास प्राप्त करने को लोग बावले हैं, भोग की चाहत में, अपने विलास की तुप्ति के लिए प्रेम उनको एक हथियार सा लगता है। स्नेह को वे माध्यम बना लेते हैं। ऐसे लोगों का इरादा सिर्फ किसी तरह देह जिसको देखने से, जिसके बारे में सोचने तक पहुंचना होता है, जबकि प्रेम देह से

जीने की राह कॉलम पं. विजयशंकर मेहता जी की आवाज में मोबाइल पर सुनने के लिए 9190000072 पर मिस्ड कॉल करें।

# गरीबी हटाओ की नहीं, अमीरी लाओ की जरूरत

#### संदर्भ... फैसलों में साहसी मानसिकता दिखाने पर ही प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की सफलता निर्भर



गुरचरण दास लेखक और स्तंभकार

दिनों पहले रविवार की रात एक टीवी शो में एंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के लक्ष्य का तिरस्कारपूर्व बार-बार उल्लेख किया। यह शो हमारे शहरों के दयनीय पर्यावरण पर था और एंकर का आशय आर्थिक प्रगति को बुरा बताने का नहीं था, लेकिन ऐसा ही सुनाई दे रहा था। जब इस ओर एंकर का ध्यान आकर्षित किया गया तो बचाव में उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि तो होनी चाहिए पर पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता पर दर्शकों में आर्थिक वृद्धि के फायदों को लेकर अनिश्चतता पैदा हो गई होगी।

कई लोगों ने बजट में पेश नीतियों व आंकड़ों को देखते हुए इस साहसी लक्ष्य पर संदेह व्यक्त किया है। मोदी ने अपने आलोचकों को 'पेशेवर निराशावादी' बताया है। किसी लक्ष्य की आकांक्षा रखने को मैं राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छी बात मानता हूं। जाहिर है कि मोदी 2.0 सरकार नई मानसिकता से चल रही है। यह खैरात बांटने की 'गरीबी हटाओ' मानसिकता से हटकर खुशनुमा बदलाव है। राहुल गांधी ने जब मोदी 1.0 पर स्ट-ब्रुट की सरकार होने का तंज कसा था तो वह 'गरीबी हटाओं से ग्रस्त हो गई थी और इसके कारण हाल के आम चुनाव में इस मामले में नीचे गिरने की होड़ ही मच गई थी। इस लक्ष्य ने आर्थिक वृद्धि की मानसिकता को

बहाल किया है, इसीलिए मोदी 2014 में चुने गए थे। समृद्धि आने के साथ प्रदूषण घटने लगता है और उसके 🛮 है। किसानों को वितरण (एपीएमसी, अत्यावश्यक वस्तु चीन में देंग शियाओ पिंग की मिसाल रखते हुए मैं तो मोदी 2.0 के लिए 'न सिर्फ गरीबी हटाओ बल्कि अमीरी लाओ' के नारे का सुझाव दूंगा। 'सूट-बूट' के प्रति सुधारवादी प्रधानमंत्री का सही उत्तर यह होना चाहिए, हां, मैं हर भारतीय से चाहता हूं कि वह मध्यवर्गीय सूट बूट की जीवनशैली की आकांक्षा रखे'। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट (सकल घरेलू उत्पाद)। यह मोटेतौर पर किसी अर्थव्यवस्था की कुल संपदा दर्शाता है। इसे औद्योगिक युग में अर्थशास्त्रियों ने ईजाद किया था और इसकी अपनी सीमाएं हैं। आज कई लोग पर्यावरण हानि के लिए आर्थिक वृद्धि को दोष देते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार धन का पीछा छोड़ लोगों की परवाह करना शुरू करे। लेकिन, यथार्थ तो यही है कि जीडीपी नीति-निर्माताओं के लिए श्रेष्ठतम गाइड है। हाल के वर्षों में आर्थिक वृद्धि ने दुनियाभर में एक अरब से ज्यादा लोगों को घोर गरीबी से उबारा है।

केवल आर्थिक वृद्धि से ही किसी समाज में जॉब पैदा होते हैं। सरकार को टैक्स मिलता है ताकि वह शिक्षा (जो अवसर व समानता लाती है) और हेल्थकेयर (जिससे पोषण सुधरता है, बाल मृत्युदर घटती है और लोग दीर्घाय होते हैं) पर खर्च कर सके। मसलन, भारत में आर्थिक वृद्धि ने ग्रामीण घरों में सब्सिडी वाली रसोई गैस पहंचाई ताकि वे घर में कंडे व लकडी जलाने से होने वाले प्रदूषण से बच सकें। 1990 में प्रदूषण का यह भीषण रूप दुनियाभर में 8 फीसदी मौतों के लिए जिम्मेदार था। वृद्धि और समृद्धि आने से यह आंकड़ा करीब आधा हो गया है। जब गरीब राष्ट्र विकसित होने लगते हैं तो बाहर का प्रदूषण तेजी से बढ़ता है पर

पास इसे काबू में रखने के संसाधन भी होते हैं। अचरज नहीं कि प्रतिव्यक्ति ऊंची जीडीपी वाले राष्ट्र मानव विकास व प्रसन्नता के सूचकांकों पर ऊंचाई पर होते हैं।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में आर्थिक वृद्धि को जॉब से अधिक निकटता से जोड़ने का मौका गंवा दिया। मसलन. उन्हें एक मोटा अनुमान रखना था कि अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 105 लाख करोड़ रुपए खर्च करने से कितने जॉब निर्मित होंगे। चूंकि आवास अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक श्रम आधारित है तो उन्हें बताना चाहिए था कि '2022 तक सबको आवास' के लक्ष्य के तहत कितने जॉब पैदा होंगे। 5 लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में सफलता साहसी सुधार लागू करने के साथ मानसिकता में बदलाव पर निर्भर होगी। 1950 के दशक से विरासत में मिला निर्यात को लेकर निराशावाद अब भी मौजूद है और वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा मामूली 1.7 फीसदी बना हुआ है। निर्यात के बिना कोई देश मध्यवर्गीय नहीं बन सकता। हमें दर्भाग्यजनक संरक्षणवाद को खत्म करना चाहिए, जिससे र्देश 2014 से ग्रसित है। हमें अपना नारा बदलकर 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' कर लेना चाहिए। केवल निर्यात के माध्यम से ही हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए ऊंची नौकरियां व अच्छे दिन आएंगे। दूसरी बात, वृद्धि और जॉब निजी निवेश के जरिये ही आएंगे। बड़े निवेशकों को भारत का माहौल प्रतिकूल लगता है। बजट ने इसे और बढ़ाया है और शेयर बाजार के धराशायी होने का एक कारण यह भी हो सकता है। तीसरी बात, हालांकि भारत कृषि उपज का प्रमुख निर्यातक बन गया है पर यह अब भी अपने किसानों से गरीब देहातियों की तरह व्यवहार करता

अधिनियम आदि को खत्म करें), उत्पादन (अनुबंध पर आधारित खेती को प्रोत्साहन दें), कोल्ड चेन्स (मल्टी ब्रैंड रिटेल को अनुमति दें) की आजादी और एक स्थिर निर्यात नीति चाहिए। सुधार पर अमल ही काफी नहीं है, मोदी को उन्हें लोगों के गले भी उतारना होगा। शुरुआत अपनी पार्टी, आरएसएस और संबंधित भगवा संगठनों से करें और उसके बाद शेष देश। मार्गरेट थैचर का यह वक्तव्य प्रसिद्ध है कि वे अपना 20 फीसदी वक्त सुधार लागू करने में लगाती हैं और 80 फीसदी वक्त उन्हें स्वीकार्य बनाने में लगाती हैं। नरसिंह राव, वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे पूर्ववर्ती सुधारक इसमें नाकाम रहें। जबर्दस्त जनादेश प्राप्त मोदी को अपनी कुछ राजनीतिक पूंजी इस पर खर्च करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि भारत चुपके से सुधार लाना बंद करे। लोकतंत्र में जीतने वाले का हनीमून आमतौर पर 100 दिन चलता है। इकोनॉमी के लक्ष्य के आलोचकों को सर्वोत्तम जवाब यही होगा कि उक्त अविध में कुछ नतीजे दिखा दिए जाएं। मसलन, पहले कार्यकाल से भू व श्रम सुधार बिल बाहर निकाले, उनमें सुधार लाएं और उन्हें इस लक्ष्य से स्वीकार्य बनाएं कि इस बार वह राज्यसभा से पारित हो जाएं। वित्तमंत्री को सार्वजनिक उपक्रमों (एयर इंडिया के अलावा) की बिक्री की समयबद्ध योजना सामने रखकर अपने साहसी विनिवेश लक्ष्य पर तेजी से अमल करना चाहिए। इस तरह के कदमों से जीडीपी लक्ष्य के प्रति लोगों का भरोसा पैदा होगा। हर तिमाही में राष्ट्र के सामने प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मोदी 2.0 के विजन में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## सरकारों का स्वभाव है गिरना ...और वे गिर ही जाती हैं



मध्यप्रदेश सहित कई इलाक़ों में बारिश लम्बे समय से आ नहीं रही है और उधर कर्नाटक में कुमार स्वामी के सिर पर ओले गिर पड़े। गिरना ही था। दरअसल, सरकारें होती ही गिरने के लिए हैं। कभी आधे-अधूरे चुनावी वादों की खोह में गिरती हैं। कभी भ्रष्टाचार की खंदक में पड़ी मिलती हैं। कभी किसी दूसरी सरकार को गिराने के लिए गिरती हैं, तो कभी, कहीं ख़ुद की सरकार बनाने के लिए गिरती जाती हैं। कुल मिलाकर गिरना उनका स्वभाव है। मोरारजी की सरकार इसलिए

किस्सा कुर्सी का था, के प्रिंट जला देने वाले संजय गांधी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से इनकार कर दिया था। चंद्रशेखर की सरकार इसलिए गिरा दी गई थी कि हरियाणा पुलिस के दो सिपाही राजीव गांधी के निवास के आसपास जासूसी करते पाए गए थे। कारण होते हैं, पर गढ़े हुए।

खैर कर्नाटक सरकार इसलिए गिरी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उन्होंने क़तरा-ब्योंता आंकड़ा जुटाया था। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही थी लेकिन जनता दल एस और कांग्रेस ने मिलकर संख्या बल जुटा लिया और सरकार बना ली थी। कांग्रेस के सवालों से ख़ुद कुमारस्वामी भी महीनों से परेशान चल रहे थे। जब लीडर परेशान हो तो टीम का बिखरना तय होता है। यही कर्नाटक में हुआ। 15-16 विधायक भाजपा की गोद में जा बैठे और सरकार गिर

गई। अब कर्नाटक के बाद राजनीतिक हलकों में जो चर्चा हो रही है, वह ग़ज़ब है। चर्चा ये है कि बारिश और मध्य प्रदेश सरकार में मुक़ाबला चल रहा है। गिरने का ...कि पहले कौन गिरे! यहां ज्यादातर इलाकों में न बारिश गिर रही है। न सरकार।

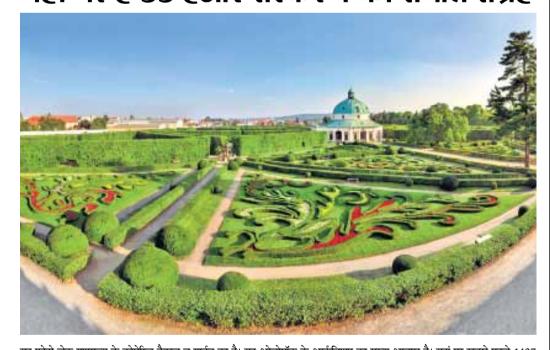
खैर सरकारों का क्या? जैसे बनती हैं, वैसे ही गिर भी जाती हैं। लेकिन बारिश का मामला अलग है। जहां गिरती है, जमकर गिरती है। देश के कई शहरों को भारी बारिश के कारण नजला हो रहा है। बारिश रुके तो जम जाता है। बारिश शुरू हो तो बहने लगता है। बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालात हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई हिंदी प्रदेश सूखे पड़े हैं। कांग्रेस की तरह। कर्नाटक में सरकार से हाथ धोना पड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है। खैर, अभी कुछ सूखे राज्यों में मौसम बारिश का है, लेकिन माहौल गर्मी

जैसा है। धप लगे आकाश में दिन में चांद नजर आता है। सन्नाटे में लिपटी दोपहर है और उसका एकाकीपन दुर करने बारिश का कोई एक भी छींटा नहीं पड़ रहा। आसमान बुझता नहीं और चांदनी रोशन रहती है। फलक पर अभी भी तारे जगमगा रहे हैं, जैसे ऊपर आसमान पर किसी ने जरी- गोटे का काम किया हो।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी रोज झूठी निकलती है। आज बारिश की संभावना बताई जाती है और दूसरे दिन तारीख आगे बढ़ जाती है। भाई लोग तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। बारिश न हुई जैसे कर्नाटक का फ़्लोर टेस्ट हो गया। आज-कल करते-करते स्पीकर महाराज ने हफ़्ते से भी ज्यादा निकाल दिया था। आख़िर भारी दबाव के चलते 23 को वोटिंग करानी ही पड़ी। सुखे पड़े राज्य भी इसी तरह के दबाव का इंतजार कर रहे हैं। कब दबाव बढ़े और कब बादल बरसें !

### वेब भारकर

#### को को मेरिज कैसल है कला का खजाना यहां पर है 33 हजार संस्करण का संगीत संग्रह



यह फोटो चेक गणराज्य के क्रोमेरिज कैसल व गार्डन का है। यह ओलोमॉक के आर्कबिशप का मुख्य आवास है। यहां पर सबसे पहले 1497 में बिशप स्टानिसलास थुर्जो ने अपना आवास बनाया था। यूरोप के सबसे खराब समय थर्टी ईयर्स वार (1618 से 1648) के दौरान 1643 में स्वीडन की सेना ने यहां भारी लूटपाट की और इसे नुकसान पहुंचाया। 1664 में ताकतवर लिचटेंसटेन परिवार से जुड़े बिशप ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 1752 में यहां भीषण आग लगी। इसके बाद इसका एक बार फिर रिनोवेशन किया गया और उस समय के प्रमुख कलाकारों फ्रांज एंटोन और जोसेफ स्टर्न ने अपनी कलाकृतियों से इसे सजाया। यहां पर प्रसिद्ध पेंटर वैसीलियो ( अंग्रेजी नाम टाइटन ) की पेंटिंग द प्लाइंग ऑफ मरस्यास भी लगी हुई है। इस महल में एक बहुत ही शानदार संगीत संग्रह है, जिसमें संगीत के 33 हजार वॉल्यूम हैं।

#### इंदेरिक... फिजूलखर्ची के खिलाफ ₹17 हजार में की शादी

अक्सर लोग अपनी शादी में क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। कई लोग तो इसके लिए उधार तक ले लेते हैं। लेकिन, सफोक के न्यू मार्केट की कीले बोगुले और सेबस्टियन ने तय किया कि वे सिर्फ 200 पाउंड (करीब 17 हजार रुपए) में ही अपनी शादी करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। इन दोनों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी शादी में इतना खर्च न करें कि उन्हें अपनी नई जिंदगी का पहला साल ही कर्ज में बिताना पड़े।

कीले और सेबस्टियन ने अपनी शादी में फोटोग्राफी के लिए एक दोस्त को तैयार किया और एएसओएस मार्केट प्लेस से सिर्फ 10 पाउंड की ड्रेस खरीदी। शादी का केक भी किसी ने डोनेट कर दिया। दो बच्चों की मां कीले बताती है कि उसने अपने शूज पर भी सिर्फ 10 पाउंड ही खर्च किए। वह खुद ही गाड़ी चलाकर रजिस्ट्री ऑफिस गई। यही नहीं उसने इस मौके पर



आए 35 अतिथियों को विवाह समारोह के बाद एक इटालियन रेस्टोरेंट में भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनसे अपने भोजन के लिए योगदान करने को कहा।

कीले और उनके अमेरिकी पति सेबस्टियन कहते हैं कि उनका यह दिन एकदम शानदार रहा और अब वे अपने रिश्तेदारों को भी समझा रहे हैं कि वे भी शादी का बजट कम करें। शादी के समय छह माह की गर्भवती कीले ने कहा कि हम

इस मौके पर कुछ भी बड़ा और खर्चीला नहीं करना चाहते थे। कीले एक व्यवसायी है और उसका पति अमेरिकी एयरफोर्स में है। वह कहती है कि अगर आपके पास धन है और आप महंगी शादी का खर्च उठा सकते हैं तो ऐसा करें, लेकिन मैं ऐसे लोगों को इसके लिए उत्साहित नहीं करना चाहूंगी, जिनकी शादी का पहला साल अधिक खर्च की वजह से कर्ज में गुजरे। जब आप शानो-शौकत पर धन खर्च करते हो तो यह आपके लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए होता है। कीले ने जूतों और कपडों पर 20 पाउंड खर्च करने के अलावा 80 पाउंड अंगूठी पर और 100 पाउंड समारोह पर खर्च किए। सेबस्टियन कहता है कि हम चाहते तो याादी पर और भी खर्च कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की फिजूलखर्ची हो। सेबस्टियन ने खुद अपना पुराना सूट ही इस मौके पर पहना। • dailymail.co.uk

#### कानून के बिना हर व्यक्ति को गरिमा के साथ पानी उपलब्ध कराना और जल संरक्षण कठिन चुनौती

# जल सुरक्षा कानून से ही सबको मिल सकेगा पानी



• राजेन्द्र सिंह, पर्यावरणविद

संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह भीषण जल संकट का सामना कर रहे देश के लिए उम्मीद जगाती है। किंतु शायद उन्हें पता नहीं है कि जब समाज मिलकर जल संरक्षण का कोई कार्य करता है तो सिंचाई विभाग का कानून अडचन बन जाता है। यह कानून हटेगा तभी जल संरक्षण के काम को सच्चा प्रोत्साहन मिल सकेगा।

लोगों को जल

एक अन्य पहलू यह है कि संविधान हर नागरिक को जीवन का हक देता है, इसलिए जीवन के लिए जल दिलाने वाले कानून की तत्काल जरूरत है। खाद्य सरक्षा कानून की तर्ज पर जल सुरक्षा कानून होगा तो समाज जल संरक्षण को अपना कर्तव्य एवं अधिकार मानकर जल संरक्षण व सामुदायिक प्रबंधन में जुट जाएगा। इस कानून के बिना व्यक्ति को गरिमा के साथ पानी उपलब्ध कराना कठिन चुनौती है। यदि समय रहते इस चुनौती पर ध्यान नहीं दिया तो समाज टुटकर विखंडित हो

जाएगा। पानी के आंदोलन की बात करते वक्त स्वच्छता अभियान की याद आती है। स्वच्छ भारत और पानीदार भारत में मूलभूत अंतर है। स्वच्छता हमारे व्यवहार और की संरक्षण को देन होती है, परंतु पानी तो प्राण है। कई तरफ घर की छत के जल के संरक्षण हेतु कानून बना हुआ है। उसका उपयोग इसलिए नहीं होता, क्योंकि शहरों में नल का जल सस्ता है, इसलिए लोग इस कानून का पालन नहीं करते। भ्रष्टाचार के कारण इस कानून का पालन कराने का प्रयास भी नहीं होता।

जल पर सभी का अधिकार होता है पर गंदगी पर किसी का अधिकार नहीं है। गंदगी से मुक्ति को सभी तैयार हैं, क्योंकि कोई भी अपना कचरा देने को सदैव तैयार रहेगा। पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानून के बिना भी देश स्वच्छ हो सकता है, लेकिन पानीदार भारत का आरंभ कानून से ही होगा। कोकण व मेघालय में देश का सबसे ज्यादा वर्षाजल होने के बाद भी जलसंकट है। सरकारी कानून और समाज की भागीदारी दोनों को बराबरी से हकदारी और जिम्मेदारी सनिश्चित करनी होगी तभी यह पानीदार भारत बनेगा। जल से जन को जोड़ने का आह्वान करने वाली प्रधानमंत्री की मन की बात अच्छी शरुआत है पर आगे बढने के लिए जल के ठेकेदारों से मुक्ति भी जरूरी है। ठेकेदार का लाभ, शुभ

को खा जाता है। पानी तो पुण्य कर्म है, इसमें लाभ नहीं चलेगा केवल शुभ टिकेगा।

दनियाभर में जल के संदर्भ में शोधन, पनर्शोधन और पुनःउपयोग- इन तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है। भारत की कानून-कायदे हैं, जो जल संरक्षण में बाधक हैं। इनके में इसके लिए छह शब्द हैं। जल सम्मान, अनुशासित और अब भी वे डर से कोई जल संरक्षण का कार्य नहीं करता। दूसरी उपयोग, प्राकृतिक पुनर्जीवन इनमें और जुड़ जाते हैं। यही भारत का विशिष्ट जल ज्ञान, व्यवहार, संस्कार को जीवन मूल्यों के साथ जोड़ता था। अभी हम यह भूल गए हैं। सरकार जनशक्ति को जलशक्ति के लिए काम करने हेतु प्रेरित करने में जुटी है। इसकी सफलता राज-समाज से जुड़कर होगी। जल के लिए जन जुड़े, भूजल भरे. जलस्तर ऊपर आएगा। तब नदिया सदानीरा बनकर बहेंगी। मिट्टी की नमी से धरती का बुखार कम होगा। मौसम का मिजाज सुधरेगा। इस सदी का यही जरूरी काम है। जल से ही जलवायु परिवर्तन अनुकूलन होगा। जल पर संपूर्ण जीवन का अधिकार की कानून-व्यवस्था होगी तो जलशक्ति हर घर में होगी। तब जल मिलेगा और पानीदार भारत बनेगा। हमने देशभर में पानी एवं पर्यावरण पर काम करने वाले विषय विशेषज्ञों से लगातार तीन साल तक विचार-विमर्श करके जल सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया है। इसमें एक हजार से अधिक विशेषज्ञों से राय ली गई। देशभर में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर इस कानुन पर संगोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अब पहल सरकार को करनी है।

## नॉलेज **भारकर** इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें-III

## ऑनलाइन रिटर्न के लिए आपका पैन ही है यूजर आईडी

https://

पर

जाकर खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके संबमिट करने के बाद आपको आपकी ई-मेल

आज ऑनलाइन रिटर्न भरना आसान हो गया है। कई वेबसाइट इनक्म टैक्स रिटर्न और टैक्स भरने में मदद करती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।



अपलोड तरीकाः इसके लिए आप https:// www.incometaxindiaefiling.gov.in/ home पर जाकर संबंधित असेसमेंट साल के लिए आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। इसके बाद अपनी आय, टैक्स भुगतान और कटौती की जानकारी जमा कर लें। प्री-फिल बटन दबाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, टैक्स भुगतान/टीडीएस इसमें भर लें। सभी डाटा भरने के बाद कैलकुलेट बटन पर क्लिक करें और अपनी टैक्स व ब्याज के बारे में अंतिम गणना को हासिल करके देख लें कि आपने रिफंड लेना है या और टैक्स देना है। अगर आपको टैक्स देना है तो उसका तत्काल भुगतान कर देयराशि को शून्य पर ले आएं। इसके बाद अपने कंप्यूटर पर इनकम टैक्स रिटर्न

incometaxindiaefiling.gov.in

के डाटा को एक्सएमएल फॉरमेट में सेव कर लें। ई-फायलिंग वेबसाइट पर दोबारा लॉगइन करें और अपलोड रिटर्न बटन दबाएं। उचित

लिए आपका पैन ही आपकी यूजर आईडी और फोन पर दो अलग-अलग ओटीपी आप दो तरह से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अपलोड करके या फिर सीधे ऑनलाइन । आईटीआर, साल सलेक्ट करें और कंप्यूटर पर सेव की गई एक्सएमएल फाइल को अपलोड कर दें। इसके बाद अगर लागू हो तो डिजिटल

खुल लाएगा। आपको उसे भरना होगा। इसको

सिगनेचर सर्टीफिकेट (डीएससी) को अपलोड कर दें। सबमिट बटन को दबा दें। सफलता पूर्वक जमा होने के बाद आईटीआर-V दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। यह आपकी रजिस्टर्ड मेल पर भी आता है। अगर आईटीआर डीएससी के साथ दाखिल किया है तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।

अगर रिटर्न डीएससी के साथ दाखिल नहीं किया है तो आईटीआर-∨ का प्रिंट लेकर उसे दस्तखत करें और 120 दिन के भीतर केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) बेंगलुरु को भेज दें। आपके रिटर्न की प्रक्रिया इसके वहां पहुंचने के बाद ही शुरू होगी। इसके लिए अपनी ईमेल या एसएसएस चेक करते रहें।

होगी। वेरिफिकेशन के बाद रिजस्ट्रेशन फॉर्म मिलेंगे। इन्हें भरने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अपनी रजिस्टर्ड ई-मेल पर आए एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करने पर आप ई-फायलिंग वेब साइट पर पहुंच जाएंगे।

> ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 80 सी का ब्योरा। सेलरी इनकम के लिए सेलरी स्लिप व फार्म-16 और एचआरए के लिए किराए की रसीद। आवासीय संपत्ति से आय की जानकारी के लिए पता. होम लोन और अगर संपत्ति किराए पर

है तो उससे होने वाली आय की

जानकारी।

• इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आवश्यक दस्तावेज :

लिए अलग-अलग वर्गों के लिए पैन, बैंक अकाउंट का ब्योरा, पिछले साल का रिटर्न, टीडीएस सर्टीफिकेट, अगर लागृ हो तो फायनेंसियल स्टेटमेंट और के तहत किए गए निवेश और 80 डी के तहत दिए गए डोनेशन